LOK SABHA DEBATES

FIRST DAY OF THE SEVENTH SESSION OF THE FOURTH LOK SABHA

LOK SABHA

Monday, February 17, 1969/Magha 28, 1890 (Saka).

The Lok Sabha met at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

Shri K. Kamaraj (Nagercoil)
Shri Janeshwar Misra (Phulpur)
Shri Jai Singh (Hoshiarpur)

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 17th February, 1969 (Hindi and English versions).

PRESIDENT'S ADDRESS

संसद् सदस्यगण, संसद् के दोनों सदनों के इस मिले-जुले सैशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सरकार के लिये यह उचित अवसर है कि वह इस वर्ष की वास्तविक स्थिति को सामने रखे और अगले वर्ष में अपनी नीतियों और उद्देश्यों की मोटी रूप-रेखा बताए।

2. हमारे गणराज्य के इतिहास में पिछला वर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा था और हम उससे अभी निकल ही पाए हैं। हमारे देश-वासियों ने जिस साहस और धीरज के साथ कठिनाइयों को झेला, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। उनके त्याग, सहयोग, मेहनत, लगन और देशभक्ति की भावना के बगैर केन्द्र और राज्य की योजनाएं और कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते थे।

3. हमारी आर्थिक प्रगति के मार्ग में जो निशान दिखाई दिए हैं, और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ये हैं—खेती-बाड़ी की पैदावार में निश्चित बढ़ौतरी, उद्योग के बड़े भाग में उन्नति, कीमतों में कमोबेश स्थिरता और शोधन संतुलन में स्पष्ट सुधार।

4. 1967-68 की फसल से हमारी खेती की पैदावार में एक मोड़ आया। अनाज का उत्पादन 9 करोड़ 56 लाख मीट्रिक टन हुआ जोकि 1964-65 के मुकाबले में 60 लाख मीट्रिक टन अधिक था। जूट, कपास, तेल के बीज, चाय, कॉफी और गन्ने जैसी तिजारती फसलें भी अच्छी रहीं। कई राज्यों में सूखा और बाढ़ के कारण जो नुक्सान हुआ था, उसके बावजूद यह आशा की जाती है कि 1968-69 में अनाज का उत्पादन उतना ही अच्छा होगा जितना कि 1967-68 में हुआ था। हमारे किसान वैज्ञानिक कृषि को तेजी से अपनाते चले जा रहे हैं। वे सिंचाई के लिए जमीन में पानी निकालने और

खेती-बाड़ी की मशीनें खरीदने के लिये भारी तादाद में पूंजी लगा रहे हैं। 1968-69 में 85 लाख हैक्टेयर जमीन पर अधिक उपज वाली फसलें बोई जाएंगी और अगले वर्ष उसका और भी विस्तार किया जाएगा। 1968-69 में 61 लाख हैक्टेयर और ज़मीन पर खेती की जाएगी।

5. सरकार किसानों को काफी मात्रा में रसायनिक खाद देगी और बड़े पैमाने पर उसका आयात भी करेगी और इस तरह उनका हौसला बढ़ाएगी। गोरखपुर, नामरूप और कोटा में नए प्लांट चालू करके भी देसी खाद तैयार की जा रही है। अगले वर्ष के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि कानपुर, दुर्गापुर, कोचीन और बड़ौदा की खाद योजनाएं चालू हो जाएंगी। देश में ट्रेक्टर बनाने पर लाइसेंस की पाबंदी हटाने से ऐसी आशा की जाती है कि ट्रेक्टरों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस बीच सरकार ने किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से ट्रेक्टर मंगाने का इन्तजाम कर दिया हैं। इस कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। रिजर्व बैंक आफ इन्डिया की देख-रेख में सहकारी संस्थाएं और कमर्शल बैंक इस काम को कर रहे हैं। अगले दो या तीन वर्षों के अन्दर बाहर से अनाज की सहायता न लेने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ ही महीनों में 30 लाख मीट्रिक टन अनाज का बफर-स्टाक तैयार हो जाएगा। 1967-68 में जो फसल हुई थी, उसमें से 64 लाख मीट्रिक टन अनाज लिया जा चुका है। अनाज सुरक्षित रखने और उसका भंडार तैयार करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की है। यह मुमकिन हो सका है कि अनाज के लाने ले जाने पर पाबंदियों में ढील दे दी जाए और खास-खास अनाजों के लिये क्षेत्रों का विस्तार कर दिया जाए।

6. सरकार ने विकास का जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें परिवार नियोजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम का विस्तार बड़े पैमाने पर अब देहाती आबादी तक हो गया है और उनमें बहुत दूर के इलाके भी शामिल हैं।

7. 1967-68 के दौरान खेती की अच्छी पैदावार से राष्ट्रीय आमदनी पिछले वर्ष के मुकाबले 9.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। ताजा अनुमानों से पता चलता है कि 1967-68 में वास्तविक राष्ट्रीय आमदनी 16,665 करोड़ रुपए थी (1960-61 के मूल्यों पर) जबकि 1966-67 में यह आमदनी 15,272 करोड़ रुपए थी। इससे मालूम होता है कि इस वर्ष राष्ट्रीय आमदनी में 1,393 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। हालांकि चालू वर्ष में कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की सीमा तक ही महदूद रहा, तो भी उद्योग में उत्पादन के सुधार से राष्ट्रीय आमदनी बढ़ने की आशा हो गई है।

8. उद्योग में भी उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले दो वर्षों में जिन उद्योगों का आधार कृषि था, उनमें कच्चे माल की कमी रही। कृषि में अधिक कार्य करने से और खेतों की आमदनी बढ़ जाने से कृषि-प्रधान उद्योगों में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे। रासायनिक खाद, कीड़े मारने की दवाइयों और ट्रैक्टर वगैरह का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। बिजली अधिक पैदा की जा रही हैं और बिजली की मशीनों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के क्षेत्र में, सूती कपड़े और वनस्पति का अधिक उत्पादन होने लगा है। लेकिन मशीन वाले कुछ उद्योगों में बनी हुई चीजों की मांग उनकी क्षमता के मुकाबले में नाकाफी रही है। 1968 के पहले नौ महीनों में उद्योग उत्पादन का इन्डैक्स मोटे तौर पर (1960 : 100) 159.3 था, जोकि जनवरी-सितम्बर 1967 के स्तर से 5.6 फीसदी ऊंचा था। वर्तमान संकेतों के आधार पर ऐसा मालूम होता है कि इस वर्ष के दौरान इस इन्डैक्स में 5 से 6 फीसदी तक वृद्धि होगी।

9. खेती-बाड़ी और कल कारखानों में उत्पादन के बढ़ने का देश की बेरोजगारी की

समस्या पर अच्छा असर पड़ा है। दो वर्षों तक सूखा पड़ने के असर को दूर करने और हालात को सुधारने में हमें अभी देर लगेगी। हमें खास तौर पर तकनीकी माहिरों की बेरोज़गारी को दूर करने की बड़ी चिंता है। क्वालीफाइड इंजीनियरों को 'एक खुद को काम पर लगाने की योजना' के अन्तर्गत काम दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

10. कृषि उत्पादन के बढ़ने से यह समस्या खड़ी हो गई है कि किसान को खेती से पैदा की गई चीजों की मुनासिब कीमत मिले। फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया की कोशिशों का यह नतीजा है कि अनाज मोल लेने की कीमतों का स्तर आज वही है जो पिछले वर्ष था। उत्पादन के बढ़ने से कीमतों में स्थिरता आयी है। थोक कीमतों का इन्डैक्स, जो कि एक वर्ष हुआ 211 था, अब 205 है।

11. निर्यात के क्षेत्र में और आयात कम करने के प्रयास में हमारी सफलतायें उत्साहजनक रही हैं। हमारी लगातार यह कोशिश रही है कि आयात की जाने वाली चीजों की जगह देसी चीजें इस्तेमाल की जायें और ऐसी नावाजिब तौर पर बड़ी-बड़ी इनकी फहरिस्तों को कम किया जाय इसका नतीजा यह हुआ कि 1968-69 के पहले नौ महीनों में सिर्फ 1,376,49 करोड़ रुपये का माल आयात किया गया। यह पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़ों के मुकाबले में 107.72 करोड़ रुपये कम है। दूसरी तरफ निर्यात करने से हमें 1,019.04 करोड़ की आमदनी हुई, यह रकम पिछले वर्ष इन्हीं महीनों में किये गये निर्यात से लगभग 116.65 करोड़ रुपये अधिक थी। इस वर्ष इंजीनियरी के सामान का नुमायां तौर पर निर्यात हुआ। कपड़ा उद्योग ने भी अधिक मात्रा में अपना निर्यात बढ़ाया है। अब हम पालिश किये हुए नगीनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने जा रहे हैं।

12. हमारे उद्योगों की बनी हुई चीजें, खासतौर से इस्पात, इस्पात की बनी चीजें, बिजली का सामान, चमड़े की चीजें और कुछ कैमिकल चीजें अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले में बहुत कामयाब रही हैं और औद्योगिक देशों की उन मण्डियों में जहां मुकाबला ज्यादा है और एशिया तथा कई अरब देशों की मण्डियों में भी उन्हें काफी लाभ पहुंचा है। विदेशों से हमें जिन चीजों की आवश्यता पड़नी है, उनकी अदायगी के लिये हमने अपने प्राकृतिक और औद्योगिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों के कारण विकासशील देशों के निर्यात से होने वाली आमदनी के बढ़ने में रुकावट पड़ रही है।

13. सरकार को मालूम है कि अदृश्य खाते के साधनों को बढ़ाने में परिवहन, जहाजरानी और पर्यटन का बड़ा महत्व है। हमारे व्यापारी जहाजी बेड़े का आकार लगभग 20 लाख टन (जी. आर. टी.) है और लगभग 7 लाख टन तैयार करने का आर्डर है। भारवाहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेड़े की रचना में विविधता लायी जा रही है। देश में ही जहाज़ बनाने का काम धीरे-धीरे बढ़ रहा है और आशा की जाती है कि इस साल के दौरान कोचीन के दूसरे जहाजों के कारखाने में काम शुरू हो जायेगा।

14. विदेशों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये कई योजनायें चालू की गई हैं, खास तौर से महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर अच्छे किस्म के होटलों में रहने का अच्छा इन्तजाम किया जा रहा है। हमारे अन्तर्राष्ट्रीय और देश के अन्य हवाई अड्डों पर ठोस तरीके से सुधार का काम किया जा रहा है।

15. देश में सिंचाई और बिजली की बड़ी मांग है। देश में सिंचाई के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिये एक अखिल भारतीय सिंचाई कमीशन बनाने का विचार है। यह कमीशन इस बात की रिपोर्ट देगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भूतल और भूगर्भ जल संसाधनों का किस तरह पूरे तौर पर विकास हो सकेगा। हालांकि पिछले बीस वर्षों

में बिजली पहले से लगभग छह गुना मिलने लगी है, फिर भी, देश के कई भागों में उसकी माँग उत्पादन क्षमता से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है वर्तमान क्षमता का ठीक उपयोग करने के लिये सरकार बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसके वितरण की योजनाओं पर और हर क्षेत्र में बिजली के सिस्टम को पूर्ण रूप से चलाने और क्षेत्री ग्रिड तैयार करने पर भी अधिक ध्यान दे रही है। इसके अलावा फालतू बिजली से पड़ौसी क्षेत्र में जहां बिजली की कमी है उसको पूरा करने के लिये टाई लाइन्स भी बनाई जा रही हैं। इस तरह आखिर में एक अखिल भारतीय ग्रिड बन कर तैयार हो जायेगा। देहातों में बिजली पहुंचाने के काम को भी विशेष स्थान दिया जा रहा है क्योंकि इससे किसान को अपनी पैदावार बढ़ाने में लाभ मिलेगा।

16. योजना कमीशन चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे रहा है यह योजना अगले अप्रैल से आरम्भ हो जायगी। अगर हमारी योजनायें हमारे राष्ट्र की इच्छा और उसके दृढ़ निश्चय की तरजुमानी नहीं करतीं और लोगों की आवश्यकताओं और सुलभ संसाधनों के फरक को पूरा नहीं करतीं तो वे केवल भविष्य की नाम मात्र रूपरेखा बनकर रह जायेंगी। उनमें हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप भविष्य का निर्माण करने के प्रयत्नों की कोई झलक दिखाई न देगी। सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है कि हमें अपनी बचत, उद्यम और प्रबन्धक योग्यता के साधन जुटाने की पूरी कोशिश करनी होगी। देहाती इलाकों में जो नई खुशहाली दिखाई देती है उसे इस तरह काम में लाना होगा जिससे कि खास तौर पर छोटे किसान पैदावार बढ़ा सकें और निसबतन पिछड़े इलाकों में तरक्की होने लगे। पब्लिक और प्राईवेट सैक्टरों में ज्यादा पूंजी लगाने की गरज से हमें वास्तविक बचत को बढ़ावा देना होगा और इसका उपयोग केन्द्र तथा राज्यों की माली हालत को मजबूत बनाने में करना होगा।

17. सरकार को इसकी जानकारी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के बहुमुखी विकास में हमारे पब्लिक सैक्टर को कितना महत्वपूर्ण पार्ट अदा करना है। इसके फलस्वरूप, सरकार इस सैक्टर की कार्यक्षमता बढ़ाने पर बराबर ध्यान लगाये हुए है। सरकारी क्षेत्र उद्यम के विषय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया गया है। इन उद्यमों के प्रबन्धकों को अधिक शक्ति प्रदान करने पर इस उद्देश्य से बहुत से फैसले किये गये हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता और लाभ उठाने की शक्ति बढ़ सके। इन उद्यमों के लिये प्रबन्ध सम्बन्धी साधन जुटाने के लिये कदम भी उठाये गये हैं, जिनमें कर्मचारियों और मजदूरों से सम्बद्ध मामलों पर समुचित नीतियां बरतना भी शामिल है।

18. विदेशी सहायता के विषय में बड़ी अनिश्चितता आ गई है। विदेशी कर्जे का बोझ बढ़ रहा है और इस वर्ष 51 करोड़ 40 लाख डालर हो गया है। कन्सार्टियम के देशों और इन्टरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमैंट ने 10 करोड़ 10 लाख डालर के कर्जे की अदायगी की जो नई व्यवस्था की है, उसका हम स्वागत करते हैं है। हम आशा करते कि हमें पर्याप्त विदेशी सहायता मिलती रहेगी। इसके साथ ही हम ऐसी नीति पर चलना चाहते हैं कि विदेशों से मिलने वाले कर्ज का अच्छी तरह उपयोग किया जाय और आत्म-निर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए धीरे-धीरे विदेशी सहायता का सहारा लेना कम कर दिया जाय।

19. यह कुछ सन्तोष की बात है कि महाराष्ट्र राज्य में तारापुर नामक स्थान पर भारत का पहला अणु बिजलीघर जुलाई 1969 से 380 मेगावाट बिजली देना आरम्भ कर देगा। बिहार में जादुगुडा मुकाम पर भारत के पहले यूरेनियम खान और कारखाने ने यह काम चालू कर दिया है और वहां यूरेनियम के कंसेंट्रेट्स का उत्पादन होना शुरू हो गया है। हमारे अणु बिजली कार्यक्रम के लिए इन कंसेंट्रेट्स से तैयार किए जाने वाले ईंधन तत्वों के लिए

हैदराबाद में कारखाना लगाने का काम शुरू हो गया है। स्पेस रिसर्च के काम में भी काफी तरक्की हुई है। 'रोहिणी' और मौसमी राकेटों को आकाश में छोड़ कर एक कामयाब तजरबा भी किया गया है। इन राकेटों का डिज़ाइन भारत में ही तैयार किया गया है और ये पूरे तौर पर यहीं बनाये गये हैं। अब भारत ने उपग्रह संचार क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। पूना के पास आरवी में भारत का पहला 'कमर्शल उपग्रह संचार भूमि केन्द्र' बन रहा है। आशा है कि अक्तूबर 1969 के आखिर तक यह केन्द्र काम करना आरम्भ कर देगा।

20. सरकार को मालूम है कि देश में पूरे तौर से आर्थिक विकास की समस्याओं के हल के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और नागालैंड की विधान सभाओं के चुनाव काफी हद तक अच्छे ढंग से और शान्तिपूर्ण वातावरण में हुए हैं। यह संतोष की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आवश्यक समझ कर केवल 28 चुनाव केन्द्रों में दोबारा मतदान करने या नये सिरे से चुनाव करने का आदेश दिया है। ये केन्द्र पांच राज्यों के उन एक लाख दस हजार से भी अधिक चुनाव केन्द्रों में से हैं, जहां लगभग दस करोड़ बीस लाख मतदाताओं से हाल ही में अपना मत डालने के लिए कहा गया था। कई जगहों से चिंताजनक सूचना मिली है कि लोगों पर दबाव धमकी के रूप में डाला गया जिसके कारण वे अपना मतदान नहीं दे सके। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है हरेक राजनीतिक दल को राजनीतिक स्थिरता बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि वह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये बहुत जरूरी है। इस बीच में हम आशा करते हैं कि चुनावों के बाद, जो अभी खत्म हुए हैं, राजनीतिक दलों के सहयोग से स्थायी सरकारें बन सकेंगी। चूंकि संगठित राजनीतिक पार्टियों से दलबदली के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, इसलिए एक समिति बना दी गई थी कि वह लोक सभा में पास किये हुए प्रस्ताव को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार करे। इस समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसकी सिफारिशों पर संसद् में विचार किया जाएगा।

21. पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों की चर्चा की थी जिन से हमारे राष्ट्रीय कार्यों में बाधा पड़ी। प्रांत, क्षेत्र, जाति और संप्रदाय के आधार पर किये गये आन्दोलनों के कारण देश में तनाव बढ़ा और हिंसात्मक घटनाएं हुई। जून 1968 में श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बहुत से विरोधी दलों के नेता और अन्य बड़े-बड़े नेतागण शामिल हुए थे। उस मीटिंग में राष्ट्रीय एकता और खास तौर से सांप्रदायिक तनाव की समस्या पर विचार-विमर्श हुआ था। एकता परिषद् ने कई खास सिफारिशें की हैं जिन पर केन्द्र और राज्यों की सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। परिषद् की सिफारिशों के अनुसार, "अपराध एवं निर्वाचन नियम (संशोधन) बिल 1968" संसद् के सामने हैं। जब यह बिल पास होकर कानून की शकल में आ जाएगा, तब इससे सांप्रदायिकता की बुराइयों को मिटाने में सरकार के हाथ मजबूत हो सकेंगे। हालांकि कानूनी और इन्तजामी तरीके बरतने जरूरी हैं, फिर भी हमारे सभी लोगों को इन बुराइयों के खिलाफ-लड़ते रहना चाहिये। सफलता इसी में है कि लोगों के दिल और दिमाग में नेशनलिजम और सैक्युलेरिजम का जजबा पैदा किया जाय।

22. देश को कुछ इन्तेहा पसंद राजनीतिक दलों की तरफ से भी हिंसा का खतरा है। इन दलों ने जिन सिद्धान्तों को सामने रखा है, वे स्पष्ट रूप से हमारे संविधान और कानून के खिलाफ़ हैं। वे ठीक तरह से सरकार चलाने और प्रगति करने में बाधक हैं। लोकतांत्रिक समाज में ऐसे किसी दल के लिए कोई जगह नहीं है जो हथियारों की मदद से विद्रोह करके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश में लगा हुआ हो।

23. माननीय सदस्यों को मालूम है कि 1966 में सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बढ़ाने और उनकी शिकायतों को दूर करने की गरज से स्वेच्छा के आधार पर एक संगठन "ज्वाइंट कनसलटेशन एण्ड कम्पलसरी आरबीट्रेशन" बनाया गया था सरकार को पूरा विश्वास है कि आपसी परामर्श और अनिवार्य पंच-निर्णय की योजना पर अमल करने से ही सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद तय हो सकेंगे, लेकिन इसके साथ यह जरूरी है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखा जाए और आवश्यक सेवाएं बेरोकटोक जारी रखी जाएं। उनका यह इरादा है कि इस योजना को कानूनी आधार दे दिया जाए ताकि वह मजबूत पाए पर खड़ी रह सकें।

24. कई बरसों तक धैर्यपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद, पिछले वर्ष असम के पुनर्गठन के बारे में एक फ़ार्मूला तैयार किया था। असम राज्य के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने के लिए संसद को आवश्यक अधिकार देने की गरज से एक संविधान संशोधन बिल संसद् के सामने पहले ही रखा है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संसद् इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी और राज्यों की विधान सभाएं इसका अनुमोदन कर देंगी तब सरकार इस योजना पर अमल करने के लिए एक कानून सामने लाएगी जिसमें पूरा ब्योरा दिया होगा।

25. अपने देश के आंतरिक मामलों की चर्चा करके मैं अब संक्षेप में विदेशी मामलों की चर्चा करना चाहूंगा। सरकार इस बात से आश्वस्त हैं कि मोटे तौर पर उस की विदेश नीति का ढांचा पक्का है और उसके सिद्धान्त निश्चित रूप से खरे उतरे हैं। आज की दुनिया में, सभी देशों के बीच शांतिपूर्ण सहजीवन, शांति को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण सहयोग, विश्व में आर्थिक खुशहाली और स्थिरता का कोई और विकल्प नहीं है। हरेक देश को निरंतर यह कोशिश करनी चाहिए कि वह आपस में सहमति के क्षेत्र का निरंतर विस्तार करे ताकि समय-समय पर उठ खड़ी होने वाली कठिनाइयों और झटकों के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया बेरोक-टोक चलती रहे।

26. संसार के बहुत से देशों के साथ भारत के सम्बन्ध कुल मिलाकर मजबूत हुए हैं और सुधरे हैं। हमरा यह पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान बड़ा परिश्रम करके भारत के खिलाफ जो अविश्वास और संदेह फैलाता है और चीन अपनी विचारधारा की प्रिजम के जरिए हमारे देश का जो चित्र तोड़-फोड़ कर पेश करता है, ये दोनों ही, स्थिति की असलियत के सामने धराशायी हो जाएंगे। सरकार ने कई मौकों पर सफाई और ईमानदारी के साथ यह कहा है कि वह प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता के अनुरूप और एक दूसरे के अन्दरूनी मामलों में बिलकुल दखल न देने के आधार पर अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहती है।

27. वियतनाम के विषय में सरकार का दृष्टिकोण साफ रहा है। इस दृष्टिकोण का आधार हमेशा यह रहा है कि वहां जो ताकतें काम कर रही हैं, उनका सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसी भी कठिनाइयां आएं, इस बात का पक्का इरादा होना चाहिए कि वे बातचीत के जरिए दूर कर ली जायंगी। यह बातचीत आजकल पेरिस में चल रही है, वियतनाम के जिन बहादुर लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली हैं, उन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भाग्य का खुद निर्णय करने देना चाहिए। पश्चिम एशिया की स्थिति का तकाजा है कि विश्व के उस भाग में होने वाले संकट को तत्काल दूर किया जाए। 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद् में जो प्रस्ताव पास किया गया था, उस पर अमल करने में देरी नहीं की जानी चाहिए। सरकार को आशा है कि सोवियत संघ, अमरीका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच आजकल जो बातचीत चल रही

है, उससे इस क्षेत्र में जल्दी ही शांति स्थापित होगी ।

28. हमारी नितियों का सब से बड़ा उद्देश्य यह है कि संबंधों को मजबूत किया जाए और अन्तर्राष्टीय सहयोग को बढ़ाया जाए, मेरी और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं का यही उदेश्य रहा है। पिछले वर्ष मैं नेपाल, सोवियत संघ, हंगरी और यूगोस्लाविया गया था। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलयेशिया और सिंगापुर की यात्रा के अलावा, प्रधानमंत्री अर्जन्तीना, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, गुयाना त्रिनिदाद और टोबागो और बेनेजुला भी गई थीं। इन सभी देशों में मेरा और प्रधान मंत्री का जो स्वागत किया गया, वह इस बात का सबूत है कि ये राष्ट्र भारत का कितना आदर करते हैं। प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में भाषण दिया था और यह बड़े संतोष की बात है कि उसमें भारत की विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत बताए गए थे, उनका व्यापक और हार्दिक स्वागत हुआ। प्रधान मंत्री ने लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भी भाग लिया। उस सम्मेलन में जो बहुत से राज्य-प्रमुख और प्रधान मंत्री इकट्ठे हुए थे, उनके साथ उन्हें विचारों का आदान-प्रदान करने का अच्छा अवसर मिला।

29. हमें भी बहुत से देशों और सरकारों के प्रमुखों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में, ईरान के महामहिम शहनशाह आर्यमेहर और शाहबानो, श्रीलंका, बुल्गारिया और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री भारत आए थे।

30. हमारी सरकार और हमारा सारा देश शांति के लिए उत्सुक है और उसे बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इसके बावजूद हमें रक्षा की तैयारी में भी बहुत सावधान रहना है हमारी हथियारबन्द सेनाओं को नए सिरे से लैस करने और उन्हें आधुनिक बनाने में काफी प्रगति हुई है। हमारी जंगी फौजों को अच्छी ट्रेनिंग दी गयी है और उनके हौसले बुलन्द हैं। हमारे सिपाहियों, नाविकों और हवाबाजों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय बरते गए हैं। उनके वेतनमान बढ़े हैं और पैंशन की शर्तों में भी सुधार किया गया है। उनके कुछ भत्तों के दरों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही रक्षा खर्च में कमी करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है।

31. आई० एन० एस० "नीलगिरि" पहला फ्रिगेट है जो हमारे देश में बना है और जिसे हाल ही में जल में उतारा गया है। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण तरक्की का निशान है।

32. हमारे आंतरिक और विदेशी मामलों का विवेचन करते समय यह जरूरी है कि उन कानून सम्बन्धी और अन्य कार्यों की चर्चा की जाए जो कि आपके सामने रखे जाएंगे।

33. 1969-70 के अगले माली वर्ष के लिए भारत सरकार की आमदनी व खर्च के अनुमानों का ब्योरा आपके विचार के लिए जल्दी ही रखा जाएगा।

34. सरकार इस सैशन में ये वैधानिक कार्य संसद् के सामने लाने की प्रस्थापना करती है :

(क) वर्तमान अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए बिल :—

(1) परिसीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1968।

(2) लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968।

(3) सीम शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969।

(4) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969।

(ख) नये बिल :—

(1) कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए

संयुक्त परामर्श और वैवश्यक माध्यस्थम के तंत्र के लिए कानूनी आधार का उपबंध करने के लिए विधेयक ।

(2) भारती कृषि अनुसंधान परिषद् विधेयक, 1969 ।

(3) आवश्यक वस्तु(संशोधन) विधेयक, 1969 ।

(4) चाय (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

(5) जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 ।

(6) दिल्ली मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1969 ।

(7) कुछ केन्द्रीय श्रम अधिनियमों का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर करने के लिए विधेयक ।

(35) मैं इस भाषण को अब यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष हम गांधी जी की जन्म-शताब्दी मना रहे हैं । हमारे मन में बहुत से विचार, भावनाएं और नक्श उभर रहे हैं और हमारे देश का पूरा इतिहास आंखों के सामने आ रहा है । हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं । हमारा देश साधनों से भरपूर है । हमारे देशवासी अच्छे कलाकार हैं । हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी लोग कुछ उन श्रेष्ठ लोगों में से हैं जिनपर कोई भी देश गर्व कर सकता है हम अपने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए अच्छे साधनों और तरीकों पर तर्क और समझदारी की सीमा में रह कर एक-दूसरे के साथ बहस तो कर सकते हैं, पर हम सब इस में एक हैं कि मिलकर गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण करें और हर आदमी का दुख दूर करने, हर आंख का आंसू पोंछने की कोशिश करें । इस तरह से ही हम जनसाधारण की सेवा कर सकेंगे और इस विशाल गणराज्य की जिन महान पुरुषों ने नीव रखी है, उनके वचनों को पूरा कर सकेंगे । आप सब इस प्रयास में सफल हों, यही मेरी शुभ कामना है ।

जै हिन्द !

Members of Parliament, it gives me great pleasure to welcome you to this joint session of the two Houses of Parliament. It is an appropriate occasion for Government to present a realistic appraisal of the year under review and to delineate the broad features of Government's policies and purposes in the coming year.

2. A year ago, we were just emerging from the worst period of economic set back in the history of our Republic. The manner in which our people faced the difficulties with courage and fortitude is a matter for pride. Without their sacrifice and co-operation, their hard work, their basic good sense and patriotism, the plans and programmes of the Central and State Governments could not have borne fruit.

3. The milestones passed on the road to our economic recovery can be easily identified. These are : a decisive upward turn in agriculture, a recovery in a large segment of industry, the relative price stability and a striking improvement in the balance of payments.

4. The harvest of 1967-68 has been the turning point in our agricultural production. Foodgrains reached a record figure of 95.6 million tonnes which was 6 million tonnes higher than the previous peak of 1964-65. Commercial crops like jute, cotton, oilseeds, tea, coffee and sugarcane also did well. Despite the damage caused by drought and floods in several States, the overall production of foodgrains in 1968-69 is expected to be as good as in 1967-68. Our farmers are increasingly taking to scientific agriculture. They are also making massive investments in ground-water exploitation for irrigation and in purchase of agricultural machinery. The high-yielding varieties programme will spread to 8.5 million hectares during 1968-69 and will be further extended next year. More intensive cropping patterns than prevailing at present are being adopted. An additional area of 6.1 million hectares of gross cropping will be achieved in 1968-69.

5. Government are supporting the enthusiasm of the farmer by providing sufficient fertilizers even by large-scale imports. Indigenous production is also building up with commissioning of new plants in Gorakhpur, Namrup and Kota. Next year, fertilizer projects at Kanpur, Durgapur, Cochin and

Baroda are expected to come on stream. With the delicensing of tractor manufacture in the country, the production of tractors is expected to be stepped up. Meanwhile, Government have undertaken to meet the needs of the farmer by imports. Large-scale credit is crucial to the programme. This is being provided by the co-operative movement and the commercial banks under the guidance of the Reserve Bank. The national objective to eliminate reliance on food aid over the next two or three years is well within reach. A buffer stock of 3 million tonnes will be reached in the course of the coming months. 6.4 million tonnes of food-grains have been procured out of the 1967-68 crops. Government have provided large funds for the preservation and storage of grains. It has been possible to relax restrictions on the movement of foodgrains and to expand the zones for particular cereals.

6. In Government's strategy of development, the family planning programme continues to occupy pivotal importance. The programme has now been widely extended to the rural population covering even remote areas.

7. The striking improvement in agriculture during 1967-68 raised national income by 9.1 per cent over the previous year. Quick estimates show that the net national income for 1967-68 amounted to Rs. 16,665 crores (at 1960-61 prices) as compared to Rs. 15,272 crores in 1966-67, recording an increase of Rs. 1,393 crores during the year. Though during the current year agricultural production will be at about the same level as in the previous year, the recovery in industry is expected to improve the national income.

8. In industry the process of recovery has begun. In the past two years, the agriculture-based industries faced shortages of raw materials. With increased activity in agriculture and an increase in farm incomes, industries oriented towards agriculture have begun to recover. Fertilizers, pesticides, tractors, etc., are increasing output rapidly. Electricity generation and the output of electrical machinery is also increasing. In the consumer goods field, cotton textiles and vanaspati production has been rising. However, the demand for the products of some industries in the machine-building sector continues to be inadequate in relation to the capacity available. The crude index of industrial production (1960 : 100) for the first nine months of 1968 stood at 159.3 which is 5.6 per cent higher than the level recorded during January-September 1967. On the basis of present trends, an increase of 5 to 6 per cent in the index seems likely during the year.

9. Growth in agriculture and industry is having a salutary effect on the unemployment problem in the country. We have still a long way to go to offset the effect of the two drought years and to improve on the position especially about unemployment amongst technologists which is causing serious concern. A modest start has been made with the programme for employment of qualified engineers in a self-employment programme.

10. The improvement in agricultural production has raised the problem of maintenance of reasonable prices for agricultural produce to the farmer. Procurement prices have, by and large, been maintained at last year's remunerative levels through the effort of the Food Corporation of India. The improvement in industrial production has resulted in price stability. The index number of wholesale prices, which was 211 a year ago, now stands at 205.

11. The performance in the field of exports and in the drive for reduction in imports has been even more encouraging. Continuing import substitution and reduction of unduly large inventories have brought the import bill for the first nine months of 1968-69 to Rs. 1376.49 crores, that is, Rs. 107.72 crores less than for the same period last year. Our export earnings, on the other hand, amounted to Rs. 1019.04 crores, that is, about Rs. 116.65 crores more than for the corresponding period of the last year. There has been striking progress in the export of engineering goods. The textile industry too has been able to raise its exports sizeably. We are also now on the way to becoming the world's largest exporter of polished gems.

12. Our industrial products, particularly steel, steel manufactures, electrical equipment, leather goods and some chemicals, have successfully met international competition and

secured substantial gains in the difficult markets of industrial nations and also in the markets of several Asian and African countries. We are beginning to utilise our natural and industrial resources to pay for what we need from abroad. However, international commercial policies continue to inhibit the expansion of export earnings of developing countries.

13. Government are aware that transport, shipping and tourism are important and vital elements in augmenting its resources on invisible account. The size of our merchant fleet is in the range of 2 million tonnes GRT with about 7 lakh tonnes on order. The fleet composition is being diversified taking into account the need for bulk carriage. Steady progress has been maintained in indigenous ship-building and it is hoped that in the course of the year, work on the second shipyard at Cochin will be commenced.

14. Various schemes have been started to attract foreign tourists and, in particular, hotel accommodation of the right type at important tourist centres is being developed further. Substantial improvements are being developed further. Substantial improvements are being effected in our international airports and other airports in the country.

15. The demand for irrigation schemes and power schemes in the country is large. It is proposed to set up an All India Irrigation Commission to review the development of irrigation in the country and to report on the best programme of integrated development of surface and ground water resources for maximising agricultural production. Though in the last two decades the availability of power has gone up nearly six-fold, demand continues to outstrip the generating capacity in some areas of the country. For better utilisation of the capacity already created, Government are giving more attention to transmission and distribution schemes and the regional grids for integrated operation of the power systems in each region. Inter-regional tie lines are also under construction for utilising surplus power in one region in a neighbouring deficit region. This will ultimately result in an all India grid. Rural electrification which is of direct benefit to the agriculturist for increasing his production, has been given a special place in the power programme.

16. The Planning Commission is finalising the Fourth Five-Year Plan which will begin its term next April. Our plans would only be indicative of the future without any attempt to shape the future to suit our needs and aspirations, unless they embodied our national will and determination to progressively bridge the gap between the needs of the people and the resources in sight. Government are determined to make every effort to mobilise our own resources of savings, enterprise and managerial ability. The new prosperity in the rural areas will have to be harnessed to promote further growth particularly among the smaller farmers and in the relatively backward regions. While encouraging a greater flow of genuine savings to sustain larger investment both in the public and the private sectors the situation will have to be utilised to strengthen the financial position of both the Centre and the States.

17. Government are conscious of the important role which our public sector has to play in the many-sided development of our economy. Consequently, the raising of the efficiency of this sector is engaging Government's close attention. The recommendations of the Administrative Reforms Commission made in their report on "Public Sector Undertakings" have been considered. Various decisions have been taken to delegate more powers to the management of these enterprises with the object of improving their efficiency and profitability. Steps have also been taken to mobilise managerial resources for these enterprises, including adoption of suitable policies of personnel and labour matters.

18. There is considerable uncertainty with regard to external assistance. The burden of servicing the external debt is mounting and amounts to 514 million dollars this year. The re-scheduling of debt payments of 101 million dollars provided by the Consortium countries and the International Bank for Reconstruction and Development is, therefore, welcome. While we hope that adequate external assistance will be forthcoming, we intend to pursue a policy of a judicious use of credits from abroad and to reduce progressively the dependence on foreign aid by increasing self-reliance.

19. It is a matter of some satisfaction that India's first atomic power station at

Tarapur, in the State of Maharashtra, is expected to deliver 380 MW of electric power from July 1969. India's first Uranium Mine and Mill at Jaduguda (Bihar) have been commissioned and the production of uranium concentrates has commenced. Work has commenced in Hyderabad on the setting up of facilittes to process these concentrates into finished fuel elements required for our atomic power programme. Considerable progress has been made in the field of space research. "Rohini" and meteorological rockets, which have been completely designed and fabricated in India, were successfully tested in flight. India has entered the field of Satellite Communications. The first Indian Commercial Satellite Communications Earth Station is under construction at Arvi near Poona. This station is expected to become operational by the end of October 1969.

20. Government are conscious that the problems of integrated economic development in the country require political stability. The elections to the Legislative Assemblies of Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Nagaland have been conducted by and large in a peaceful and orderly atmosphere. It is a matter of satisfaction that the Chief Election Commissioner has found it necessary to order repoll or fresh poll in only 28 polling stations out of over 1,10,000 polling stations in the five states in which an electorate of nearly 102 million was recently called upon to cast its vote. However, disquieting reports have been received from certain areas that sections of citizens were subjected to pressures amounting to intimidaiion which prevented them from exercising their franchise. This matter is receiving Government's attention. Every political party should endeavour to ensure dolitical stability which is essential for rapid social and economic development. In the meantime we hope that with the co-operation of all the political parties, stable governments will be formed after the elections whoich have just concluded. As defections from organised political parties contributed to political instability, a Committee was appointed to examine this problem in pursuance of a resolution passed by the Lok Sabha. The Committee has completed its work. Its recommendations will now be considered by Parliament.

21. Last year, I referred in my speech to certain disturbing trends in our national affairs Parochial, regional caste and communal movements have caused tensions and violence in the country. The National Integration Council consisting of representatives of the Central and State Governments, leaders of many opposition parties and other leaders of public opinion, held a meeting in Srinagar in June 1968 to consider problems of national integration, and in particular that of communal tensions. The Council made a number of specific recommendations on which action is being taken by the Central and State Governments. The Criminal and Election Laws (Amendment) Bill, 1968, introduced in pursuance of the recommendations of the Council, is before Parliament. When enacted, it will greatly strengthen the hands of the Government in curbing the evils of communalism. However, while legal and administrative measures are necessary, the fight against these fissiparous movements has to be carrie'd to the broad masses of our people. The key to success lies in fostering the concept of Indian Nationalism and secularism in the minds and hearts of our people.

22. The country also faces the danger of violence from certain extremist political groups. The doctrines propounded by these groups are clearly subversive of our Constitution and the rule of law, and detrimental to orderly government and progress. There is no place in a democratic society for groups which seek to change the social and political structure by armed insurrection.

23. As the Hon'ble Members are aware, the Machinery for Joint Consultation and Compulsory Arbitration was set up on a basis in 1966 with the object of promoting harmonious relations between Government and their employees and the redressal of employees' grievances. Government have full faith that the Scheme of Joint Consultation and Compulsory Arbitration is the only answer two the problem of settlement of disputes with its employees consistent with the imperative need for the maintenance of discipline in the public services and un-interrupted operation of essential services. They accordingly propose to give the Scheme a statutory basis in order to place it on a firmer and sounder footing.

24. After years of patient deliberations, a formula was evolved last year for the reorga-

nisation of Assam. A Constitution Amendment Bill for conferring necessary within the powers on Parliament to set up an autonomous State with in the state of Assam is already before the House. After Parliament has approved this amendment and it is atified by the State Legislature, as required under Article 368, Government propose to bring forward detailed legislation to give effect to the scheme.

25. Travelling beyond the limits of our internal affairs, I should like to refer briefly to external affairs. Government feel convinced of the essential soundness of the broad structure and principles of their foreign policy. In the world today, it is difficult to see any alteernative to peaceful co-existence among all States and peaceful co-operation for the promotion of peace, ecnomic well being and stability in the world. Every State must ceaselessly strive for areas of agreement so that processes of detente can continue unimpeded even in the midst of difficulties and setbacks that may arise from time to ;ime.

26. There is an all-round strengthening and improvement of India's relations with various nations of the world. It is our firm belief that the stimulated distrust and suspicion of India assiduously spread by Pakistan, and the distorted image of our country which China projects through its ideological prism, will both succumb to the realities of the situation. Government have expressed more than once with frankness and sincerity their desire to have friendliest of relations with both our neighbours consistent with our sovereignty, territorial integrity and on the basis of absolute non-interference in each other's internal affairs.

27. Government's stand on Vietnam, which was always based on a realistic appraisal of the interplay of forces, has stood vindicated. Whatever the difficulties ahead, their must be firm resolve to overcome them through negotiations now in progress in Paris. The courageous people of Vietnam who have suffered so much should be able to fashion their own destiny without outside interference The situation in West Asia demands a most urgent solution of the continuing crisis in that part of the world. There is not much time to lose in implementing the Security Council Resolution of November 22, 1967. Government hope that the consultations now in progress between the USSR, the USA, Britain and France will lead to an early restoration of peace in the area.

28. The major aim of our policies remains the strengthening of relations and the promotion of international co-operation. This has been the purpose of the visits to foreign countries undertaken by me and the Prime Minister. I visited Nepal, the Soviet Union, Hungary and Yugoslavia last year. Apart from visits to Australia, New Zealand, Malaysia and Singapore, the Prime Minister visited Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela. The welcome accorded to me and the Prime Ninister in all these countries testifiied to the regard in which India is held by these nations. The Prime Minister addressed the General Assembly of the United Nations and it is a matter of deep satisfaction that enunciation in her address of the basic principles of india's foreign policy evoked a heartwarming, widespread response. The Prime Minister also attended the Commonwealth Prime Ministers' Conference in London. It provided a welcome opportunity for exchange of views with the large number of Heads of States and Prime Minister assembled there.

29. We have been privileged to receive many Heads of State and Governments in our midst. Most recently, Their Imperial Majesties the Shahanshah Aryamehr and Shahbanu of Iran, and the Prime Minister of Ceylon, Bulgaria and New Zealand were in India.

30. While Government and the entire country ardently desire peace and are dedicated to promoting peace, we have to be very vigilant in the matter of defence preparedness. Considerable progress has been made in reequipping and modernising our Armed Forces. Our fighting forces are in a good state of training aud their morale is high. Some measures have been taken to improve the service conditions of our soldiers, sailors and airmen. Improvements have been effected in their pay scales and in their pensionary terms and the rates of certain allowances. The need for economy in defence expenditure has always been kept in view.

31. The first frigate built in the country, INS Nilgiri, was launched recently. This is

an important landmark in the history of the Indian Navy.

32. A survey of our internal and external affairs must inevitably include a reference to the legislative and other business which will come up befoure you.

33. The estimates of receipts and expenditure of the Government of India for the next financial year 1969-70 will be presented to you for consideration shortly.

34. Government propose to bring before Parliament the following legislative measures during the current session:—

(a) Bills to replace the existing Ordinances :

(i) The Limitation (Amendment) Ordinance, 1968.

(ii) The (Public Wakfs (Extension of Limitation) Amendment Ordinance, 1968.

(iii) The Customs (Amendment) Ordinance, 1969.

(iv) The Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1969.

(b) New Bills:

(i) Bill to provide Statutory Basis for the Machinery of Joint Consultation and Compulsory Arbitration for Central Government Employees.

(ii) The Indian Council of Agricultural Research Bill, 1969.

(iii) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1969.

(iv) The Tea (Amenbment) Bill 1969.

(v) The Prevention of Water Pollution Bill 1969.

(vi) The Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1969.

(vii) Bill to extend certain Central Labour Acts to the State of Jammu & Kashmir.

CONSTITUTION (22nd Prodt.) BILL

35. I should now like to conclude this Address by recalling that this year we celebrate Gandhiji's birth centenary. Many ideas, emotions and images rise to one's mind and the whole panorama of the history of our conutry unfolds itself. We are inheritors of a great heritage. Our country is rich in resources. Our people are skilled craftsmen. Our scientists and technologists are some of the best which any country could boast of. While we can argue with one another within the limits of reason and rationality about the best means and methods to adopted for reconstructing our society, we can all unite in a purposive effort to build the India of Gandhiji's dreams and to endeavour to wipe every tear from every eye. Only thus shall we be able to serve the common people and fulfil the pledges of the founding father of this great Republic. I wish your labours all success.

12.32 hrs.

FOREIGN MARRIAGE BILL

(*i*) Report of Joint Committee

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee on the Bill to make provision relating to marriages of citizens of India outside India.

(*ii*) Evidence before Joint Committee

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN Sir, I beg to lay on the Table a copy of the evidence given before the Joint Committee on the Bill to make provision relating to marriages of citizens of India outside India.

12.33 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

Extension of time for presentation of Report of Joint Committee

SHRI SHANTILAL SHAH (Bombay-North-West) : Sir, I bag to move :—

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India, up to the 12th March, 1969."